संख्या-22/2020/517(2)/सैंतीस-2-2020-1(32)/2018

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 मार्च, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में रू0-155.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-15/2020/517/सैंतीस-2-2020-1(32)/2018, दिनांक-20.03.2020 द्वारा निर्गत की गई है। उक्त शासनादेश में अंकित लेखाशीर्षक "2403-पशुपालन-788-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0113-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम-जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.)" त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसे निम्नवत पढ़ा जायः-

"2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0113-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम-जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.)"

2- शासनादेश दिनांक-20.03.2020 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-22/2020/517(3)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मँत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in